अमर उजाला
लखनऊ, 29 जुलाई 2012
My City
लखनऊ V

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया खोलेगा एक हजार सहायक सेंटर

अब हाईस्कूल के बाद सीएमए फाउंडेशन कोर्स

अमर उजाला ब्यूरो

- मिलेगी सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन की मान्यता
- ग्रामीण व छोटे शहरी इलाकों के बच्चों के लिए तोहफा

लखनऊ। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग (सीएमए) को छोटे शहरों व ग्रामीण इलाकों में लोकप्रिय बनाने के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने नई पहल की है। अब हाईस्कूल उत्तीर्ण विद्यार्थी को भी सीएमए फाउंडेशन कोर्स करने का मौका मिल सकेगा। फाउंडेशन कोर्स के बाद मुख्य सीएमए परीक्षा में शामिल न होने वाले विद्यार्थियों को संस्थान सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन का प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिसकी मदद से लेखांकन से जुड़े कार्यों में रोजगार के अवसर मुहैया हो सकेंगे। वर्तमान में फाउंडेशन कोर्स के लिए इंटर परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। यह जानकारी इंस्टीट्यूट के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह ने शनिवार को लखनऊ में एक प्रेसवार्ता में दी।

लखनऊ चैप्टर में आए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार की मदद से ग्रामीण व छोटे शहरों में रहने वाले विद्यार्थियों को तोहफा देने के लिए नई कार्ययोजना शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके तहत देशभर में आईसीएआई जल्दी एक हजार सहायक सेंटर स्थापित करेगा। पहले चरण में यूपी के पीलीभीत, बाराबंकी, अलीगढ़, शाहजहांपुर व मेरठ शहरों को चुना गया है। इन शहरों में संचालित कॉमर्स कॉलेज के साथ अनुबंध कर इन सेंटरों को संचालित किया जाएगा। इसके माध्यम से लागत लेखांकन के क्षेत्र में कॅरिअर चुनने का सपना बुन रहे विद्यार्थियों को हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सीएमए फाउंडेशन कोर्स में प्रवेश की सुविधा मिल सकेगी।

इंस्टीट्यूट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि उक्त फाउंडेशन कोर्स के तहत जून व दिसंबर में परीक्षा कराई जाएगी। फाउंडेशन कोर्स उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी को आईसीएआई सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन का प्रमाणपत्र देगा। इसके बाद अगर अभ्यर्थी सीएमए बनने के लिए आगे की परीक्षा नहीं देना चाहे तो भी उक्त प्रमाणपत्र के आधार पर लागत लेखांकन से जुड़े क्षेत्र में बेहतर रोजगार के अवसर पा सकेगा। उन्होंने बताया कि उक्त योग्यता रखने वाले छात्रों को सरकारी स्तर पर संचालित विकास परक योजनाओं में लेखांकन कार्य के लिए वरीयता के आधार पर चयनित करने का भरोसा भी केंद्र सरकार दे चुकी है। इसीलिए आईसीएआई अब लागत लेखांकन के क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने के लिए देश भर में विशेष अभियान चला कर कॉमर्स विद्यार्थियों को इससे जोड़ेगी।

40 हजार खर्च में सौ फीसदी रोजगार

विद्यार्थी मात्र 40 से 42 हजार रुपये खर्च कर सीएमए की योग्यता प्राप्त कर सकता है और सौ फीसदी रोजगार के साथ सालाना छह से साढ़े छह लाख रुपये कमा सकता है। जबकि एमबीए व इंजीनियरिंग कोर्स की पढ़ाई में लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी बेहतर नौकरी की उम्मीद नहीं की जा सकती।

प्रदेश में शुरू होंगे तीन नए चैप्टर

लखनऊ। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया प्रदेश में जल्दी तीन नए चैप्टर शुरू करेगी। आगरा, मेरठ व वाराणसी में साल के अंत तक नए चैप्टर शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में आईसीएआई के चैप्टरों की संख्या दस हो जाएगी। इंस्टीट्यूट के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह ने शनिवार को विशेष बातचीत में बताया कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स (सीएमए) को ग्लोबल स्तरीय बनाने के लिए पाठ्यक्रम के प्रारूप में भी बदलाव लाया जाएगा। इसके तहत सीएमए की योग्यता के लिए तीन साल के व्यावहारिक प्रशिक्षण को अनिवार्य करते हुए कुछ पाठ्यक्रम की विषयवस्तु में बदलाव के साथ कुछ नए पाठ्यक्रमों को भी कोर्स में जोड़ने का फैसला हुआ है। लखनऊ चैप्टर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सेदारी करने आए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि पाठ्यक्रम के प्रस्तावित बदलाव के तहत अब सीएमए मुख्य परीक्षा के ग्रुप में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास कम्युनिकेशन व व्यावहारिक इंजीनियरिंग से जुड़ी विषयवस्तु को भी शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य लागत लेखांकन के प्रोफेशनल को कामकाज के दौरान वैश्विक स्तर पर आने वाली चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाना है। साथ ही लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फील्ड में तीन साल के व्यावहारिक अनुभव के प्रमाणपत्र के आधार पर ही अभ्यर्थी को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कोर्स में डिग्री व प्रमाणपत्र देकर स्वतंत्र प्रैक्टिस की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यूपी में बीते काफी समय से आईसीएआई के नए चैप्टर शुरू किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही थी।

फील गुड की तमन्ना

आईसीएआई के नेशनल चेयरमैन ने यूपी को फील गुड कराने की तमन्ना जताई। उन्होंने बताया कि देवरिया जिले का निवासी होने के कारण मेरी इच्छा है कि प्रदेश की बेहतरी के लिए जमीनी स्तर पर कुछ ठोस किया जाए। इसके लिए देर शाम उन्होंने ग्राम विकास मंत्री अरविंद सिंह गोप से मुलाकात कर केरल व तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर बेरोजगार युवाओं को इंस्टीट्यूट की मदद से लेखांकन क्षेत्र में क्षेत्रीय स्तर पर ही प्रशिक्षित कर रोजगार परक बनाने की कार्ययोजना पर भी चर्चा की। इस संबंध में सीएम स्तर पर आगे बातचीत का भरोसा भी दिलाया।

बदलेंगे केंद्रीय योजनाओं के मानक

आईसीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पोषित विकास व कल्याणकारी योजनाओं के मानक में जल्दी बड़े बदलाव के संकेत दिए। मनरेगा व एनआरएचएम योजनाओं में मिले पैसे को लेकर कुछ राज्यों में उजागर हुई व्यापक गड़बड़ी के बाद सरकार अब हर योजनाओं के क्रियान्वयन में लागत लेखांकन को अनिवार्य कर रही है। इसके लिए ग्राम पंचायत व ब्लॉक स्तर पर लेखा कार्य करने वालों को रखा जाएगा। जो आवंटित धन के उपयोग का लेखाजोखा तैयार कर योजनाओं के सतत अंकेक्षण कार्य में सहयोग करेंगे।